DELHI POLICE 2025

CONSTABLE HCM AWO/TPO DRIVER

यकीन बैच

POLITY

स्थानीय स्वशासन

LOCAL SELF GOVERNMENT Part -2

LIVE

01-04-2025 12:05 PM

Polity - स्थानीय स्वशासन / Local Self Goverment - Class-2

बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिसें स्वीकार / Accepted the Recommendations of Balwant Rai Mehta committee :- 12 Jan-1958

लागू :- 2 oct 1959 → राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में (1st state)

प्रयोग / Practical → Aug-1958 - आन्ध्रप्रदेश

⇒ 1959 में आन्ध्रप्रदेश में लागू ।

1960 → असम, तमिलनाडु, कर्नाटक
1962 - महाराष्ट्र
1963 - गुजरात
1964 → पं. बंगाल

'अशोक मेहता' समिति / Ashok Mehta Committee → 1977

Report → Aug 1978 → पंचायत राज - 2 स्तर में
- मण्डल स्तर → मण्डल पंचायत / Mandal panchayat
- जिला स्तर → जिला परिषद / District Council

स्वीकार नहीं किया
Not accepted

डा. पी. वी. के राव समिति या G.V.K राव समिति → 1985 :- [योजना आयोग की सिफारिश पर गठन]

Recommendations :- पंचायत राज को 4 भागों बाटा जाये :-
- स्वीकार नहीं किया

1. राज्य स्तर → राज्य विकास परिषद [S.D.C]
2. जिलास्तर → जिला परिषद (D.C)
3. मण्डल स्तर - मण्डल पंचायत (M.P)
4. ग्राम — ग्राम सभा (G.S)

डा. पी. वी. के राव समिति की अन्य सिफारिसें :- (i) वित्त आयोग | Finance Commission
(ii) पंचायतों का कार्यकाल | Tenure - 5 years.
(iii) SC/ST / महिलाओं के लिये आरक्षण की मांग की

डा. लक्ष्मीमल सिन्घवी समिति :- 1986

TP - P.Y.Q

(i) पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा / Constitutional states की मांग
(ii) पंचायत राज के चुनाव - गैर दलीय (Non-party Election होना चाहिए।
(iii) न्याय पंचायत (Nyay Panchayat
(iv) ग्राम न्यायालयों - Gram Courts
(v) वित्तीय सहायता | Financial Help.

⇒ P.K थुंगन समिति - 1988

(i) पंचायतों को संवैधानिक दर्जा

(ii) प्रत्येक 5 years राज्य वित्त आयोग [state finance commission]

(iii) पंचायतों का सम्बन्ध राज्यों से न होकर संघ (union)

⇒ राजीव गांधी सरकार द्वारा :— 64th CA - 1989 - संसद में पेश But पास नहीं हुआ।

⇒ पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार → 73वां CA - 1992 →
- लोकसभा - 22 Dec - 1992 - पास
- राज्यसभा → 23 Dec - 1992 - पास

राष्ट्रपति ने हस्ता० / Signature → 20 april - 1993

लागू - 24 april - 1993 → प्रथम राज्य → MP मध्यप्रदेश ✓

पंचायत राज अधि० - 1992

73वा संविधान संशोधन अधि - 1992 / 73th Constitutional Amendment act - 1992

- पंचायतों को संवैधानिक दर्जा / Constitutional Status मिला।
- भाग / Part - 9 पुनः / again जोड़ा गया
- Art 243 - 243'O' नये अनुच्छेद जोड़े गये।
- नयी अनुसूची / New schedule - 11 वीं जोड़ी गयी।

किस DPSP में पंचायत राज का गठन - Art 40

Art 243 a [243 क] → ग्राम सभा / Gram sabha

Art 243 b / 243 ख → ग्राम सभा / पंचायत की गठन [243 B] एवं संरचना [243 C] ✓

पंचायतों में आरक्षण / Reservation in panchayats → Art 243 D → $\frac{1}{3}$ भाग

कार्यकाल / Tenure - Art → 243 E (3) - 5 years

राज्य वित्त आयोग - 243 I

राज्य चुनाव आयोग - 243 K